रणजीत टाइम्स

इंदौर

शनिवार, 4 जुलाई, 2026

वर्ष 02 | अंक 161 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

दतिया का रण बदला, 16 साल बाद खत्म होगी 'नरोत्तम बनाम भारती' की जंग!

दतिया। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल दतिया इस बार एक नए राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है।

पिछले 16 वर्षों से जिस चुनावी मुकाबले की पहचान डॉ. नरोत्तम मिश्रा बनाम राजेंद्र भारती रही, वह इस उपचुनाव में पहली बार टूटने जा रही है।

दोनों दिग्गज आमने-सामने नहीं होंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत और प्रभाव पूरे चुनाव पर हावी रहेंगे। दतिया की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां जनता ने कभी किसी एक दल को स्थायी जनादेश नहीं दिया। अब तक हुए 15 विधानसभा चुनावों में 9 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा (पूर्व जनसंघ

सहित) और अन्य मौकों पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और समीकरणों को जीत मिली। यानी दतिया का मतदाता हमेशा स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार की स्वीकार्यता को प्राथमिकता देता रहा है।

मोहन सरकार के कार्यकाल का तीसरा उपचुनाव, बढ़ा सियासी महत्व

यह उपचुनाव केवल दतिया तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में यह तीसरा विधानसभा उपचुनाव होगा। अब तक हुए उपचुनावों में भाजपा अपनी राजनीतिक बढ़त बनाए रखने का दावा करती रही है, लेकिन हर उपचुनाव ने सरकार की लोकप्रियता, संगठन की मजबूती और सत्ता विरोधी माहौल की अलग-अलग परीक्षा भी ली है। दतिया का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाजपा के संगठन, नेतृत्व और चुनावी रणनीति की अग्निपरीक्षा माना जा रहा है। यदि भाजपा यह सीट जीतती है तो इसे मोहन सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर माना जाएगा। लेकिन यदि परिणाम विपरीत आता है तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनमत का संकेत बताने में देर नहीं करेगा। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में अपनी वापसी का अवसर है।

प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, परिवहन और विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। राजस्थान में प्रधानमंत्री सुबह जोधपुर पहुंचेंगे, जहां वे नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे तथा संशोधित उड़ान (UDAN) योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जिले के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी सहित कई विकास परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण करेंगे। यह रिफाइनरी राज्य के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात

पहुंचेंगे, जहां विभिन्न विकास एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री के दौरे को आगामी विकास योजनाओं और राज्यों में निवेश को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार आज इंदौर में

इंदौर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार 4 जुलाई को इंदौर प्रवास पर रहेंगे। वे शाम 4 बजे लता मंगेशकर सभागृह में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की बैठक में शामिल होकर उनसे संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओंकारेश्वर रवाना होंगे। अगले दिन 5 जुलाई को ओंकारेश्वर एवं महेश्वर के प्रवास पर रहेंगे। तत्पश्चात इंदौर आकर सायंकाल दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

कांग्रेस साइकिल चलाएगी... दिग्गी पैदल चलेंगे!

राजेश धाकड़

मध्यप्रदेश कांग्रेस में इन दिनों भले ही अंदरूनी उठापटक और इस्तीफों का दौर जारी हो, लेकिन पार्टी भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में भी जुटी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि घरों में धूल खा रही साइकिलों को बाहर निकालें और पैडल मारने की तैयारी शुरू करें। उनका कहना

है कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस साइकिल यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएगी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी खुद को सक्रिय बताते हुए 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक करीब 1,000 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा पूरी तरह गैर-राजनीतिक होगी, इसमें कांग्रेस का प्रचार नहीं किया जाएगा और न ही सोशल मीडिया पर इसका प्रदर्शन होगा। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1.11 लाख रुपये का चंदा दिया था, जिसकी रसीद आज भी उनके पास सुरक्षित है। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो वे अपनी चंदा राशि वापस मांगेंगे। उन्होंने यह भी अपील की कि राम मंदिर निर्माण में चंदा देने वाले श्रद्धालु भी इस यात्रा में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की साइकिल यात्रा को कितना जनसमर्थन मिलता है और दिग्विजय सिंह की पदयात्रा में कितने लोग कदम से कदम मिलाकर चलते हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए कृषक कल्याण वर्ष के कार्यक्रमों को मिशन मोड में चलाने के निर्देश

राजेश धाकड़

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खेती की लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से राजधानी से लेकर गांव तक सीधे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा सभी योजनाओं का मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं के

डिजिटलाइजेशन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने, कम पानी वाली फसलों के प्रति किसानों को जागरूक करने तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने में निजी संस्थाओं का सहयोग लेने पर जोर दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि जुलाई में ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई-पासबुक सुविधा शुरू की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव, संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल तथा इंदौर, उज्जैन, खरगौन, बुरहानपुर, जबलपुर, भोपाल, नीमच, सागर, रतलाम और नरसिंहपुर सहित विभिन्न जिलों में कृषि एवं उद्यानिकी से जुड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मानसून में निखर उठते हैं महाराष्ट्र के ये झरने

बारिश का मौसम आते ही महाराष्ट्र की वादियां हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं और यहां के झरने अपने पूरे शबाब पर नजर आते हैं।

अगर आप मानसून में प्रकृति के बीच सुकून भरा सफर करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र के ये झरने आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए। भिवपुरी वॉटरफॉल (कर्जत): मुंबई और पुणे के बीच स्थित यह झरना ट्रेकिंग और वीकेंड ट्रिप के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में शामिल है। बारिश के दिनों में यहां का नजारा बेहद मनमोहक हो जाता है।

थोसेघर वॉटरफॉल (सातारा):

करीब 500 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे झरनों में गिना जाता है। मानसून में इसकी तेज जलधारा और आसपास की हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करती है।

लिंगमाला वॉटरफॉल (महाबलेश्वर):

महाबलेश्वर की पहाड़ियों के बीच स्थित यह झरना बारिश के मौसम में अपनी खूबसूरती के चरम पर होता है। यहां से घाटियों का मनोहारी दृश्य भी देखने को मिलता है।

रंधा फॉल्स (अहमदनगर):

भंडारदरा के पास स्थित यह झरना प्रवरा नदी पर बना है। मानसून में पानी का तेज बहाव और प्राकृतिक सौंदर्य इसे फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए खास बनाता है।

कुने वॉटरफॉल (लोनावला):

तीन चरणों में गिरने वाला यह झरना लोनावला की सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक धरोहरों में से एक है। बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। यात्रा के दौरान फिसलन वाले रास्तों पर सावधानी बरतें, मौसम की जानकारी पहले से लें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। प्रकृति का आनंद लें, लेकिन पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हर पर्यटक की जिम्मेदारी है।

चंदा चोरों पर बुलडोजर की कार्रवाई कब?

लखनऊ।उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने गुरुवार को राम मंदिर चंदा चोरी के कथित मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर चंदे में गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कब होगी. या फिर छोटे लोगों पर ही कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि बुलडोजर केवल मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए ही है.राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा सरकारों पर कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है और पुलिस खुलेआम लोगों पर अत्याचार कर रही है।

उनका आरोप था कि संविधान को कमजोर करने की कोशिशें देशहित में नहीं हैं उन्होंने न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. गौतम ने कहा कि कई न्यायिक फैसलों को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय दबाव में दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आईएएस और पीसीएस अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं. चुनाव आयोग पर भी उन्होंने निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जनता यह सब देख चुकी है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि राम मंदिर की स्थापना के समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दलित होने के कारण आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री ने स्वयं मंदिर की आधारशिला रखी. उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है.।

गौतम ने मंदिर निर्माण में कथित तौर पर 40 प्रतिशत कमीशनखोरी और चंदे तथा चढ़ावे में अनियमितताओं का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि चंदे के रूप में कितना सोना-चांदी आया और उसका रिकॉर्ड क्या है, इसकी पारदर्शी जानकारी सामने नहीं आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया और इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है.राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को लेकर अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को कथित रूप से हाउस अरेस्ट किए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रदेश सरकार की आलोचना की. उनका कहना था कि भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों में सभी प्रोटोकॉल का पालन होता है, जबकि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को दर्शन और जांच के लिए जाने से रोका जाता है।

विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर बोलते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अगले एक महीने के भीतर पार्टी का संगठन पूरी तरह तैयार हो जाएगा और डेढ़ महीने के अंदर जनता का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 2027 में उत्तर प्रदेश को "योगी मुक्त" बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।

उफनती नदी के पुल को पार करते बही कार

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उफनती नदी को पार करने की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। तेंदूखेड़ा के पास नदी पर बने एक पुल को पार करते समय एक बुलेरो गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी चला रहे व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार तीन अन्य लोग जैसे-तैसे अपनी जान बचाने में सफल रहे।

नहीं लगा पाए अंदाजा

दरअसल हादसा उस समय हुआ जब बुलेरो सवार लोग वापस लौट रहे थे। रास्ते में तेंदूखेड़ा के पास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ और पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। गाड़ी में सवार लोग पुल के ऊपर बह रहे पानी की रफ्तार और गहराई का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। उन्होंने पानी के बीच से ही गाड़ी निकालने का प्रयास किया, लेकिन बीच पुल पर पहुंचते ही बुलेरो नदी के तेज और अनियंत्रित बहाव की चपेट में आ गई और बह गई।हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान रवि पिल्ले जबलपुर सदर कैंट इलाके के निवासी थे। बताया जा रहा है कि बुलेरो में सवार सभी लोग एक शराब कंपनी से जुड़े हुए थे और काम के सिलसिले में ही दौरे पर निकले थे। गाड़ी के बहते ही उसमें सवार अन्य तीन लोगों ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वर्षाकाल में उफनती नदियों और पुल के ऊपर से बहते पानी को पार करने का जोखिम कतई न उठाएं।

रणजीत टाइम्स

अन्ना के दबाव में झुकी सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की प्रस्तावित भूख हड़ताल से ठीक पहले सूचना का अधिकार (RTI) नियमों में किए गए विवादित बदलावों पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को पारदर्शिता और जनदबाव की बड़ी जीत माना जा रहा है। दरअसल, राज्य सरकार ने हाल ही में RTI नियमों में कुछ संशोधन किए थे, जिन पर नागरिक संगठनों और पारदर्शिता के पक्षधर कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अन्ना हजारे ने आरोप लगाया था कि नए नियम सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं, आम नागरिकों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ डालते हैं और अपील की व्यवस्था को कमजोर करते हैं। उनका कहना था कि इससे सरकारी जवाबदेही प्रभावित होगी और सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना को नुकसान पहुंचेगा।

हजारे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने इतने महत्वपूर्ण बदलाव जनता, सामाजिक संगठनों और RTI कार्यकर्ताओं से कोई व्यापक चर्चा किए बिना लागू कर दिए। उन्होंने मांग की थी कि विवादित नियमों को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अन्ना हजारे के आंदोलन की घोषणा के बाद सरकार ने विवाद बढ़ने से पहले नियमों के अमल पर रोक लगाने का निर्णय लिया। अब सरकार इन संशोधनों की दोबारा समीक्षा करेगी और सभी पक्षों से चर्चा के बाद आगे का फैसला लेगी। गौरतलब है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रभावी हथियार माना जाता है। ऐसे में RTI नियमों में किसी भी बदलाव को लेकर सरकारों को अक्सर नागरिक समाज और पारदर्शिता समर्थकों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है।

पानी के संकट में 20 लाख करोड़ का मौका

देश में बढ़ते जल संकट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और जल प्रबंधन क्षेत्र की कंपनियों के लिए करीब 20 लाख करोड़ रुपये के बड़े कारोबारी अवसर का रास्ता खोल दिया है। केंद्र सरकार पेयजल, सीवेज, नदी संरक्षण और शहरी जल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को आने वाले वर्षों में बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। सरकार की जल जीवन मिशन योजना के लिए हर वर्ष लगभग 67 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2026 में जल शक्ति मंत्रालय को करीब 99,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा AMRUT 2.0 के तहत शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क पर लगभग 2.99 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं नमामि गंगे फेज-II के लिए सीवेज ट्रीटमेंट और नदी पुनर्जीवन परियोजनाओं पर 22,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाइपलाइन, जल शोधन संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, पंपिंग सिस्टम और नदी पुनर्जीवन से जुड़ी कंपनियों के लिए यह दशक सबसे बड़ा विकास काल साबित हो सकता है। बढ़ते शहरीकरण, भूजल संकट और जलवायु परिवर्तन ने जल क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सरकारी निवेश और निजी भागीदारी (PPP) के बढ़ने से जल अवसंरचना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। इससे न केवल इंफ्रा कंपनियों को नए कारोबार मिलेंगे, बल्कि देश में सुरक्षित पेयजल, बेहतर सीवरेज व्यवस्था और जल संरक्षण को भी नई गति मिलेगी।

अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का पराक्रम, समुद्री डाकुओं से व्यापारी जहाज को बचाया

भारतीय नौसेना ने एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी त्वरित कार्रवाई और समुद्री सुरक्षा की क्षमता का परिचय देते हुए अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के हमले को विफल कर एक व्यापारी जहाज और उसके चालक दल को सुरक्षित बचा लिया। नौसेना की तत्परता से संभावित बड़ी समुद्री घटना टल गई।

जानकारी के अनुसार, व्यापारी जहाज से संकट का संदेश मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने तत्काल अपने युद्धपोत और समुद्री निगरानी संसाधनों को सक्रिय किया। नौसेना की मौजूदगी और त्वरित कार्रवाई के चलते समुद्री डाकू पीछे हटने पर मजबूर हो गए और व्यापारी जहाज को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया गया। भारतीय नौसेना पिछले कुछ वर्षों से अदन की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में लगातार एंटी-पाइरेसी मिशन चला रही है। इन अभियानों के तहत कई देशों के व्यापारी जहाजों को सुरक्षा प्रदान की गई है और अनेक समुद्री डकैती की घटनाओं को सफलतापूर्वक रोका गया है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इन समुद्री मार्गों से गुजरता है। ऐसे में भारतीय नौसेना की सक्रिय मौजूदगी न केवल भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा करती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय नौसेना का यह अभियान एक बार फिर साबित करता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति ही नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा का भरोसेमंद साझेदार भी बन चुका है।

अफगानिस्तान पर हमले को लेकर अमेरिका-पाक साथ, भारत की नजर

अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हालिया सैन्य कार्रवाई को लेकर क्षेत्रीय कूटनीति तेज हो गई है। 27 जून को पाकिस्तान की ओर से अफगान क्षेत्र में की गई एयरस्ट्राइक में करीब 28 लोगों की मौत के बाद विवाद और गहरा गया।

इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के उस अधिकार का समर्थन किया है, जिसके तहत वह अपने ऊपर होने वाले आतंकी हमलों से आत्मरक्षा की बात करता है। अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है। इस बयान को पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिकी समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कार्रवाई को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने लगातार यह रुख रखा है कि अफगानिस्तान की जनता के साथ मानवीय सहयोग और विकास साझेदारी जारी रहनी चाहिए। भारत का जोर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई पर रहा है। मौजूदा घटनाक्रम के बीच नई दिल्ली स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव दक्षिण एशिया की सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन के लिए नई चुनौती बन सकता है। ऐसे समय में अमेरिका के बयान ने कूटनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्षेत्रीय शक्तियों की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

सहजयोगः मन, चित्त और हृदय की निर्मलता को पाने की साधना

वर्तमान परिस्थितियों में कभी कभी मन बहुत व्यथित होता है, मन को शांत करना और विचारों में स्थिरता व सकारात्मकता स्थापित करना थोड़ा कठिन जान पड़ता है। विडंबना इस कलियुग की ये है कि इस युग में सबसे ज्यादा अशुद्ध मनुष्य का मन, चित्त व हृदय ही हैं। अनुकूल परिस्थितियां न पाकर सबसे पहले यह मन ही क्रोध से भरता है और नकारात्मक विचारों की उथल-पुथल चित्त को अशांत व गर्म कर देती है। यह परिस्थिति मनुष्य को इतना बैचेन कर देती है कि वह रातों की नींद भी खो बैठता है। धीरे-धीरे शरीर भी रोगग्रस्त होने लगता है। फिर मनुष्य अपनी आदत के अनुसार अपनी गलतियों व दोषों को भगवान अथवा दूसरे लोगों के सर मढ़ने लगता है। अपनी गलतियों के लिए भगवान को कोसने से अच्छा है कि अपने मन को ही शुद्ध बना लिया जाए। पर प्रश्न यह उठता है कि कैसे? जिस समाज में हम रहते हैं वहां का माहौल सदैव आध्यात्मिक, सुखद व सकारात्मक नहीं होता है। इसी कारण मन व चित्त को शुद्ध रख पाना मुश्किल कार्य है। पर इसे संभव बनाया जा सकता है, सहजयोग में नित्य ध्यान व सूक्ष्म चक्रों की जागृति से यह कार्य अत्यंत ही सहज हो जाता है। शुद्ध चित्त से साधक की साधना को बल मिलता है साथ ही मन में उठने वाले विचार शांत हो कर निर्विचारिता की प्राप्ति होती है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि चित्त का सहज शुद्धिकरण कैसे होता है? सहजयोग संस्थापिका श्री माताजी निर्मला देवी जी ने स्पष्ट किया है कि, पहला चक्र मूलाधार चक्र है।इस पर श्री गणेश जी की शक्ति कार्य करती है। श्री गणेश हमारे चित्त व विचारों को निर्मल व शुद्ध करते हैं। न केवल विचारों व चित्त को बल्कि वे हमारे चक्रों, नाड़ियों व हृदय को शुद्ध, पवित्र व निर्मल करते हैं। उनकी शक्ति से हम अपने विचारों को साधते हैं। वे हमारे क्रोध को भी शांत करते हैं। मां ने स्वाधिष्ठान चक्र को दूसरा महत्वपूर्ण चक्र बताया है। इस चक्र पर श्री ब्रह्मदेव व श्री सरस्वती की शक्ति कार्य करती है। श्री माताजी ने बताया है कि यह चक्र हमारे विचारों को साधने में सहायक होता है। इस चक्र की सहायता से हम निर्विचारिता को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध विद्या व परमात्मा को पाने का ज्ञान इस चक्र के शुद्धिकरण से संभव है। हम असीम शक्तियों को धारण किए हुए हैं,बस उन शक्तियों की जागृति हमें आनी चाहिए। आप यह सब सहजयोग ध्यान के माध्यम से बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। इसकी अनुभूति लेने के लिए सहजयोग ध्यान केंद्रों पर जाकर आप अपनी कल्पनाओं को प्रत्यक्ष में बदलते देख सकते हैं। नजदीकी सहजयोग ध्यान केंद्र से संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर18002700800 अथवा www.sahajayoga.org.in से प्राप्त कर सकते हैं।

भाजपा एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष नियुक्ति पर उठे सवाल, दीपक वर्मा ने जताई नाराजगी

खुशबू श्रीवास्तव कांग्रेस से भाजपा में आए भूपेंद्र चौहान को मिली कमान, पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप

इंदौर।:- भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर चल रही अटकलों पर संगठन ने विराम लगाते हुए हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भूपेंद्र चौहान को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद राजनीतिक और संगठनात्मक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इस नियुक्ति से सबसे अधिक नाराजगी लंबे समय से पार्टी के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता दीपक वर्मा ने जताई है। नगर अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे दीपक वर्मा का आरोप है कि वर्षों से संगठन के लिए निष्ठापूर्वक काम करने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर हाल ही में पार्टी में शामिल हुए व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं है। दीपक वर्मा का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत की, लेकिन नियुक्ति में उनकी सेवाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। उनका मानना है कि इस तरह के फैसलों से जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो सकता है। वहीं, भाजपा संगठन की ओर से इस नियुक्ति को संगठनात्मक निर्णय बताते हुए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की जा रही है। संगठन का कहना है कि प्रत्येक नियुक्ति संगठन के व्यापक हित और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर की जाती है। अब राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संगठन का यह निर्णय कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बढ़ाएगा या फिर सभी कार्यकर्ता संगठन के फैसले को स्वीकार कर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नियुक्ति का संगठन की आंतरिक राजनीति पर क्या असर पड़ता है और नाराज कार्यकर्ताओं का अगला कदम क्या होगा।

फर्जी शपथ पत्र के आधार पर विकास अनुमति लेने का आरोप, सतवा-बी कॉलोनी की अनुमति निरस्त

राजेश धाकड़

इंदौर। ग्राम बढ़ियाकिमा स्थित सतवा-बी (Satva B) नामक कॉलोनी की विकास अनुमति फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के आरोप में निरस्त कर दी गई है। प्रशासन ने विकास अनुमति की शर्त क्रमांक 25 एवं 31 के उल्लंघन को आधार मानते हुए यह कार्रवाई की।

मामले में आरोप है कि कॉलोनी के डेवलपर ने विकास अनुमति प्राप्त करने के लिए कलेक्टर कार्यालय के कॉलोनी सेल, टीएनसीपी (Town and Country Planning) तथा रेरा के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह जानकारी दी थी कि संबंधित भूमि से जुड़ा कोई भी मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार उसी भूमि के स्वामित्व को लेकर सक्षम न्यायालय में सिविल वाद लंबित था। इस संबंध में पीड़ित किसान परिवार की ओर से कुसुम जाट ने अपने अधिवक्ता अभिषेक रघुवंशी के माध्यम से जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि न्यायालय में विवाद लंबित होने की जानकारी छिपाकर फर्जी शपथ पत्र के आधार पर विकास अनुमति प्राप्त की गई। शिकायत की जांच के बाद प्रशासन ने विकास अनुमति की शर्तों के उल्लंघन को सही पाया और सतवा-बी कॉलोनी की विकास अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई की।

मामले में यह भी दावा किया जा रहा है कि पूर्व विधायक विशाल पटेल के पुत्र गिरिराज पटेल भी इस

कॉलोनी परियोजना में पार्टनर हैं। हालांकि इस संबंध में उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अशिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि कुछ समय पूर्व बिल्डर ने खुड़ैल थाना क्षेत्र में संबंधित भूमि का कब्जा लेकर कॉलोनी का विकास कार्य शुरू कर दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह कार्रवाई थाना प्रभारी से कथित मिलीभगत के कारण संभव हुई। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।अअब विकास अनुमति निरस्त होने के बाद इस पूरे मामले में आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

भरत राठौर बने गोर बंजारा युवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष

इंदौर गोर बंजारा दल के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन मंत्री की सर्वसम्मति से श्री भारत राठौड़ को गोर बंजारा युवा दल, मध्यप्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें इंदौर एवं खरगोन महानगर प्रभारी का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि श्री भरत राठौर के नेतृत्व में समाज के संगठन, युवा सशक्तिकरण, शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता के कार्यों को नई गति मिलेगी। इस नियुक्ति पर समाज के पदाधिकारियों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ

दिव्यानंद अर्गल

ग्वालियर :- अषाड़ मास के शुभ अवसर पर कम्युनिटी हॉल विवेक विहार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ आज शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ हुआ कलश यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति भाव से कॉलोनीयों का भ्रमण किया

कथा का वाचन परम पूज्य भागवत आचार्य सुश्री गायत्री देवी द्वारा अपने मुखारविंद से श्रोताओं को श्रवण कराएंगी यह कथा प्रतिदिन दोपहर 4:00 बजे से 7:00 तक आयोजित की जाएगी कथा के प्रथम दिवस पर कथा वाचक द्वारा श्रीमद भागवत कथा का महत्व समझाया एवं भागवत की महिमा को समझाया वहीं श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर भक्ति रस का आनंद प्राप्त किया आयोजन स्थल पर पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा इस अवसर पर विवेक विहार कॉलोनी युवा समिति के अलावा सभी विवेक विहार निवासी सदस्यगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने किया जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण

नवल किशोर

परिसर में जलभराव और गंदगी पर जताई नाराजगी, तीन दिन में ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश ओपीडी में चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति,मरीजों की सुविधा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की दी हिदायत

कटनी। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष तिवारी ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों का भ्रमण कर उपचार व्यवस्था, चिकित्सकों की उपलब्धता, स्वच्छता, मरीजों की सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में नालियों के कारण हुए जलभराव और फैली गंदगी को देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तीन दिवस के भीतर संपूर्ण ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त कर अस्पताल परिसर को जलभराव मुक्त बनाया जाए। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष मिश्रा सहित अन्य चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हर मरीज को समय पर मिले उपचार,ओपीडी में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर श्री तिवारी ने आकस्मिक चिकित्सा कक्ष, पंजीयन कक्ष, सामान्य एवं मेडिसिन ओपीडी, अस्थि रोग, दंत रोग, स्त्री रोग तथा शिशु रोग विभाग का निरीक्षण किया। अधिकांश विभागों में चिकित्सक मरीजों का उपचार करते हुए मिले। शल्य चिकित्सा ओपीडी में चिकित्सक के वार्ड राउंड पर होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी ओपीडी में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि उपचार के लिए आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मरीजों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों और उनके परिजनों के बैठने की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी एवं प्रतीक्षालयों में बैठने के लिए अतिरिक्त बेंच उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्मानजनक, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण का अधिकारी है तथा छोटी-छोटी सुविधाएं भी मरीजों के उपचार अनुभव को बेहतर बनाती हैं।

स्वच्छ अस्पताल, सुरक्षित अस्पताल

अस्पताल परिसर में जलभराव और गंदगी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने सिविल सर्जन तथा परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि नालियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार तथा परिसर की समुचित सफाई का कार्य तीन दिनों के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्षा ऋतु में अस्पताल परिसर में जलभराव की स्थिति किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगी और व्यवस्थाओं में लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।

क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी लिया जायजा

कलेक्टर ने निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि भवन के आसपास प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में जलभराव से अस्पताल की सेवाएं प्रभावित न हों। साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए।

मरीजों से सीधे जाना फीडबैक

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री तिवारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे संवाद कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों के व्यवहार और अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मरीजों की संतुष्टि ही स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक कसौटी है। इसलिए प्रत्येक मरीज को समय पर उपचार, आवश्यक दवाएं, स्वच्छ वातावरण और संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री तिवारी ने निर्देशित किया कि जिला चिकित्सालय जिले की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था है। यहां आने वाले प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण उपचार, बेहतर सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं चिकित्सकों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए।

स्कूटर से 83,800 रुपये की अवैध शराब व वाहन जब्त, महिला पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में जिला आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह गश्त के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। विभागीय टीम ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान के दौरान संदेह के आधार पर सुनीता पति रोहित बौरासी (39 वर्ष), निवासी 25/1 विनोबा नगर, बड़ी ग्वालटोली, इंदौर की होंडा एक्टिवा (क्रमांक MP09-UF-2975) की तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटर की डिक्की एवं प्लास्टिक के बोरे से देशी प्लेन मदिरा बरामद हुई। जब्त मदिरा एवं वाहन का अनुमानित बाजार मूल्य 83,800 रुपये बताया गया है। आरोपी महिला के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। जिला आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल की बाउंड्री के अंदर गिरा पेड़ बड़ा हादसा टला,मध्यान भोजन के समय की घटना स्कूल में मची अफरा-तफरी

नवल किशोर

प्राथमिक शाला मझगवा में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

कटनी। लगातार हो रही बारिश के बीच स्कूल परिसर में खड़ा एक पेड़ अचानक जड़ सहित उखड़कर बाउंड्रीवाल के अंदर गिर पड़ा। गनीमत रही कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय बच्चे मध्यान भोजन कर रहे थे और पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया। यदि कुछ पल पहले या बाद में यह पेड़ गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्

रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय तेज बारिश हो रही थी। पेड़ गिरते ही स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पेड़ बाउंड्रीवाल पर गिरने के साथ ही बिजली की लाइन भी उसकी चपेट में आ गई, जिससे विद्युत तार टूट गए। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे करंट फैलने जैसी किसी गंभीर दुर्घटना की आशंका टल गई। स्कूल प्रबंधन ने भी तत्काल बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

"महिलाओं के कानूनी अधिकार"-एक विशेष मार्गदर्शिका

महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरुक करती हुई पुस्तिका का विधायक बहोरीबंद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने किया विमोचन

कटनी । महिलाओं के कानूनी अधिकार"- एक विशेष मार्गदर्शिका जो खास रूप से महिलाओं की सुरक्षा एवं उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हुई का विमोचन बहोरीबंद के विधायक श्री प्रणय प्रभात पांडे उपस्थित जनप्रतिनिधियों और जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर की मौजूदगी में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत बड़गांव में किया गया। विधायक श्री पांडे ने उपस्थित महिलाओं के विशाल समूह से अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहने पुस्तिका को पढ़कर अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश एवं ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRIF) के संयुक्त तत्वाधान में पुस्तिका को प्रकाशित किया गया था। जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने बताया कि यह बहुउद्देशीय पुस्तिका अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक है।

भेदभाव एवं हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं हेतु पंचायत को फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में सुदृढ़ करना आवश्यक है। सुश्री कौर बताती हैं कि सरल भाषा में लिखी गई महिलाओं के कानूनी अधिकार विशेष मार्गदर्शिका में महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानूनो का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों, सचिवों, ग्राम रोजगार सहायक, स्व सहायता समूह एवं अन्य समुदाय स्तरीय संस्थाओं तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स की महिला के अधिकारों एवं सुरक्षात्मक कानून के संबंध में व्यावहारिक जानकारी होना चाहिए। इस पुस्तिका की सहायता से न्याय तक पहुंच सुगम होगी। सुश्री कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित लिंक के माध्यम से पुस्तिका की ई-प्रति को प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला एवं जनपद पंचायत स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

मार्गदर्शिका में कानूनी अधिकारों की जानकारी

"महिलाओं के कानूनी अधिकार"- एक विशेष मार्गदर्शिका में दहेज प्रतिषेध नियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2006, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986,, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, विशेष विवाह अधिनियम 1954, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम) 2013, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंध में सहज भाषा में जानकारी दी गई है।

एसपी के व्यवहार पर आप ने उठाए सवाल, कार्रवाई की मांग

ग्वालियर। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि जनसमस्याओं और न्याय की मांग को लेकर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अभद्र व्यवहार किया गया।

पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर के अनुसार, प्रदेश प्रवक्ता कुशवाह, प्रदेश यूथ अध्यक्ष जितेंद्र जैन, जिला अध्यक्ष तिलोचन सिंह, संगठन मंत्री मनोहर लाल साहू सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हरिशंकर मौर्य और पुरुषोत्तम बौद्ध से जुड़े प्रकरण में न्याय की मांग लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। पार्टी का आरोप है कि चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से "Get Out From My Office" कहते हुए कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस व्यवहार से प्रतिनिधिमंडल और न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। पार्टी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रशासनिक गरिमा के अनुरूप नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपनी शिकायत सम्मानपूर्वक प्रशासन के समक्ष रखने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने कहा कि वह जनहित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

युवा बेरोजगार, किसान परेशान और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ मोर्चा, संयुक्त पत्रकार वार्ता कर जिला व प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान

नवल किशोर

कटनी। युवाओं के भविष्य और किसानों की समस्याओं, उज्जैन भूमि प्रकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने जिला व प्रदेशव्यापी जनआंदोलन का ऐलान किया है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस की संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला एवं ग्रामीण जिलाध्यक्ष तथा पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जनता के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में लाखों युवाओं का भविष्य संकट में है। नीट और सीबीएसई परीक्षा से जुड़े विवादों तथा विद्यार्थियों की शिकायतों ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस "छात्रों की गूंज" अभियान के माध्यम से प्रदेशभर के विद्यार्थियों के बीच पहुंचेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। ग्रामीण जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि खरीफ सीजन के बीच प्रदेश का किसान खाद और बिजली संकट से जूझ रहा है। डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की कमी, खाद की कालाबाजारी, पर्याप्त बिजली नहीं मिलने तथा टोकन व्यवस्था की अव्यवस्था के कारण किसानों की

बुवाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मूलभूत समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रही है।

पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने उज्जैन भूमि प्रकरण का मुद्दा भी उठाया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और मुख्यमंत्री निर्दोष हैं तो पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा सभी तथ्य जनता के सामने रखे जाएं। साथ ही महाकाल लोक परियोजना में उठे भ्रष्टाचार और गुणवत्ता संबंधी सवालों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी जल्द ही एक विशेष डिजिटल पोर्टल शुरू करेगी, जहां प्रदेश का कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग अथवा कथित अवैध संपत्तियों से संबंधित जानकारी एवं दस्तावेज गोपनीय रूप से साझा कर सकेगा। सत्यापन के बाद इन तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन के तहत प्रदेशभर में पत्रकार वार्ताएं, "छात्रों की गूंज" अभियान, 14 और 15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक जनजागरण कार्यक्रम, 15 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव तथा जुलाई के अंतिम सप्ताह में उज्जैन में विशाल जनआंदोलन और रैली आयोजित करेगी। साथ ही विधानसभा सत्र में भी इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी का यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य, किसानों के अधिकार, पारदर्शी शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए है। उन्होंने कहा कि जब तक विद्यार्थियों को न्याय, किसानों को राहत और जनता को जवाब नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस का संघर्ष लगातार जारी रहेगा।

जान जोखिम में न डालें! ग्राम दासघाट रपटे पर पानी के तेज बहाव के बाद प्रशासन सख्त; तहसीलदार, जनपद सीईओ और पुलिस टीम ने संभाली कमान

ताप्ती नदी के बिजोरी रपटे पर बाढ़ का खतरा, खकनार प्रशासन ने रोकी आवाजाही

महेन्द्र मालवीय रणजीत टाईम्स

बुरहानपुर जिले के खकनार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिजोरी के ग्राम दासघाट में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। यहां ताप्ती नदी पर बना रपटा जो कि आस-पास के द गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। रपटे के ऊपर से तेज बहाव में पानी बह रहा है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला।

प्रशासनिक टीम ने किया निरीक्षण

खकनार तहसीलदार जितेंद्र अलावा, जनपद सीईओ सुनीता बघेल , ग्राम सचिव दीपक अंबिकर, और खकनार पुलिस विभाग से सतीश सूर्यवंशी

सहित भारी प्रशासनिक और पुलिस अमला बिजोरी ग्राम पहुंचा। अधिकारियों ने रपटे पर पानी के तेज बहाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

राहगीरों को सख्त हिदायत, रोकी गई आवाजाही

मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां से गुजरने वाले राहगीरों और ग्रामीणों को सख्त समझाइश दी। तहसीलदार और पुलिस टीम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक पानी रपटे के ऊपर से बह रहा है, तब तक कोई भी व्यक्ति जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश न करे। सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश-प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर निम्नलिखित जरूरी कदम उठाए गए हैं।

निगरानी और तैनाती

रपटे के दोनों ओर पुलिस और कोटवारों की तैनाती की जा रही है ताकि कोई भी वाहन चालक या राहगीर बाढ़ के पानी में न उतरे।

विकल्प मार्ग का उपयोग

ग्रामीणों को पानी कम होने तक धैर्य रखने और अति-आवश्यक होने पर ही सुरक्षित या वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

सतर्क रहने की अपील

प्रशासन ने तटीय इलाकों और नदी के आस-पास रहने वाले लोगों को लगातार अलर्ट पर रहने को कहा है।

इंदौर मेट्रो कॉरिडोर पर जमीन मालिकों को बड़ी राहत, एलिवेटेड-अंडरग्राउंड रूट के दोनों ओर मिलेगा TDR और अतिरिक्त FAR का फायदा

इंदौर के बहुप्रतीक्षित Madhya Pradesh Metro Rail Corporation के 32 किलोमीटर लंबे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। अब इस प्रोजेक्ट के एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों रूट पर प्रभावित होने वाले जमीन मालिकों, दुकानदारों और रहवासियों को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी TDR का लाभ मिलेगा। इसके लिए मेट्रो रूट के दोनों तरफ 500-500 मीटर तक के क्षेत्र को रिसीविंग एरिया घोषित किया जा रहा है। इस फैसले के साथ अब प्रभावित लोगों को केवल मुआवजा ही नहीं, बल्कि भविष्य में अतिरिक्त एफएआर (Floor Area Ratio) का भी लाभ मिलेगा। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने इस संबंध में मास्टर प्लान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके तहत 15 दिनों के भीतर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। यह कदम इंदौर के शहरी विकास और मेट्रो नेटवर्क विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल प्रोजेक्ट की गति बढ़ेगी बल्कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद भी कम हो सकते हैं इंदौर मेट्रो का वर्तमान प्रस्तावित रूट एयरपोर्ट से गांधी नगर, सुपर कॉरिडोर, विजय नगर, खजराना, पलासिया, एमजी रोड, रीगल, राजवाड़ा और बड़ा गणपति होते हुए वापस एयरपोर्ट तक फैला हुआ है। इसमें लगभग 20 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड रहेगा, जबकि 12 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। यह नेटवर्क शहर के सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाले हिस्सों से गुजर रहा है, जहां जमीन और संपत्तियों पर सीधा असर पड़ना तय है।

अभी तक Indore Municipal Corporation सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण कार्यों के दौरान बाधक मकानों और दुकानों को तोड़ने की स्थिति में नकद मुआवजे के बजाय TDR सर्टिफिकेट दे रहा है। अब यही व्यवस्था मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी लागू की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों की संपत्ति मेट्रो निर्माण में प्रभावित होगी, उन्हें

उनके नुकसान के बदले विकास अधिकार दिए जाएंगे, जिनका उपयोग वे शहर के अन्य हिस्सों में अतिरिक्त निर्माण के लिए कर सकेंगे या बेच भी सकेंगे। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के कई हिस्सों में स्थानीय लोगों का विरोध लगातार सामने आ रहा है। खासतौर पर जहां मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं या जहां अंडरग्राउंड खुदाई की योजना है, वहां दुकानदारों और रहवासियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कई लोग अपनी वर्षों पुरानी संपत्तियों के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में TDR का विकल्प उन्हें आर्थिक रूप से राहत दे सकता है। इसी के साथ शासन पहले ही मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पॉलिसी लागू कर चुका है। यह पॉलिसी मेट्रो कॉरिडोर के आसपास के इलाकों में मिक्स लैंड यूज और अतिरिक्त FAR देने का प्रावधान करती है। यानी अब मेट्रो मार्ग के आसपास रहने वाले और निवेश करने वाले लोगों को एक ही जमीन पर अधिक ऊंचाई तक निर्माण करने की अनुमति मिलेगी।

TOD और TDR का संयुक्त लाभ शहर के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। अभी इंदौर में सामान्य तौर पर डेढ़ से दो FAR तक की अनुमति मिलती है, लेकिन TOD पॉलिसी के तहत यह बढ़कर चार FAR तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि अब डेवलपर्स और प्रॉपर्टी मालिक कम जमीन पर अधिक निर्माण कर सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इंदौर में वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। यानी शहर का विस्तार क्षैतिज रूप से फैलने के बजाय ऊंचाई में होगा। इससे जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा और ट्रैफिक दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। मिक्स लैंड यूज के तहत एक ही क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आवासीय प्रोजेक्ट और दफ्तर विकसित किए जा सकेंगे। यह नीति केवल मेट्रो रूट तक सीमित नहीं है। पूर्व में तैयार किए गए TOD कॉरिडोर में सुपर कॉरिडोर, एबी रोड, एमआर-10 और एमजी रोड जैसे प्रमुख मार्गों को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा रेडिसन चौराहा, बंगाली चौराहा, पलासिया, बड़ा गणपति और एयरपोर्ट क्षेत्र को भी TOD जोन का हिस्सा बनाया गया है। वर्ष 2024 में शासन ने मेट्रो नेटवर्क के दोनों ओर 500-500 मीटर की चौड़ाई में तीन TOD कॉरिडोर प्रस्तावित किए थे। उस समय भी दावे, आपत्तियां और सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी की गई थी और उसके बाद मास्टर प्लान में संशोधन किए गए थे। अब उसी योजना को और आगे बढ़ाते हुए TDR को भी जोड़ा जा रहा है।

डायमंड गृह निर्माण संस्था पर बढ़ी जांच की आंच, पंजीयन बरकरार लेकिन पुराने भू-घोटाले की परतें फिर खुलीं

इंदौर में पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं और विवादों के केंद्र में बनी Diamond Grih Nirman Sanstha को लेकर कई तरह की भ्रामक जानकारियां सामने आ रही थीं। यह दावा किया जा रहा था कि संस्था का वर्षों पहले ही परिसमापन कर दिया गया था और उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। लेकिन अब सहकारिता विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि संस्था का पंजीयन अभी तक निरस्त नहीं हुआ है और न ही परिसमापन की प्रक्रिया पूरी हुई है। इसका मतलब यह है कि संस्था आज भी कानूनी रूप से अस्तित्व में है और उस पर प्रशासक की नियुक्ति भी कायम है। इस खुलासे के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। खासकर उस समय, जब इस संस्था से जुड़े बहुचर्चित भू-घोटाले में पुलिस, प्रशासन और सहकारिता विभाग ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। पुलिस जहां इस मामले में जुड़े प्रमुख नामों से पूछताछ कर रही है, वहीं दस्तावेजों की पड़ताल के जरिए जमीन के स्वामित्व, रजिस्ट्री और कब्जे से जुड़े कई अहम तथ्यों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह मामला सिर्फ जमीन के स्वामित्व विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी चोरी, फर्जी रजिस्ट्री, अवैध प्लॉटिंग और राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि वर्षों पहले जब शहरी सीमा में सीलिंग कानून लागू था, तब उससे बचने के लिए कई गृह निर्माण संस्थाएं बनाई गई थीं। इन्हीं में से एक Diamond Grih Nirman Sanstha भी थी। उस समय शासन ने ऐसी संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी में विशेष छूट दे रखी थी, जिसका मकसद आम लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना था। लेकिन बाद में इस छूट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। आरोप है कि डायमंड गृह निर्माण संस्था के संचालकों ने भी इसी छूट का फायदा उठाकर लाखों रुपये की स्टाम्प ड्यूटी बचाई और शासन को राजस्व का नुकसान पहुंचाया।

हलाला केस में हाईकोर्ट सख्त, 9 आरोपियों को राहत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला के नाम पर कथित यौन शोषण से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि शिकायत में दर्ज तथ्यों से संज्ञेय अपराध बनता है, तो पुलिस को निष्पक्ष जांच करने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी आपराधिक मामले में केवल यह तर्क पर्याप्त नहीं है कि मामला किसी व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) या धार्मिक परंपरा से जुड़ा है। यदि प्रथम दृष्टया किसी महिला के साथ अपराध होने के आरोप सामने आते हैं, तो कानून के अनुसार जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर और जांच प्रक्रिया को चुनौती देते हुए राहत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा और जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि धार्मिक प्रथा या व्यक्तिगत कानून की आड़ में किसी भी कथित आपराधिक कृत्य को न्यायिक जांच से छूट नहीं दी जा सकती। यदि किसी शिकायत में दंडनीय अपराध के पर्याप्त आधार दिखाई देते हैं, तो पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया अपने निर्धारित कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।

पाकिस्तान की जेलों में 188 भारतीय, भारत ने मांगी तत्काल रिहाई

भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 2008 के कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत अपनी-अपनी जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की ताजा सूची का आदान-प्रदान किया। इस प्रक्रिया के तहत भारत ने पाकिस्तान को अपनी हिरासत में मौजूद 382 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 57 मछुआरों, कुल 439 लोगों की सूची सौंपी।

वहीं पाकिस्तान ने भारत को 53 नागरिक कैदियों और 135 मछुआरों, कुल 188 भारतीयों की सूची उपलब्ध कराई। सूची मिलने के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी भारतीय नागरिकों और मछुआरों की शीघ्र रिहाई, सुरक्षित स्वदेश वापसी और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही भारत ने उन 13 भारतीय कैदियों तक तत्काल कांसुलर पहुंच (Consular Access) देने की भी मांग दोहराई, जिनकी राजनयिक पहुंच अब तक पाकिस्तान ने उपलब्ध नहीं कराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि जो भारतीय अपनी सजा पूरी कर चुके हैं या जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो चुकी है, उन्हें बिना देरी रिहा किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान से ऐसे कैदियों की पहचान और उनकी वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची साझा करते हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों को कानूनी सहायता, कांसुलर पहुंच और मानवीय आधार पर राहत उपलब्ध कराना है। हालांकि, दोनों देशों के रिश्तों में तनाव के बावजूद यह व्यवस्था अब भी जारी है और इसे द्विपक्षीय विश्वास बनाए रखने के महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक माना जाता है।

पीथमपुर SEZ में निवेश की बड़ी उड़ान, 2245 करोड़ के चार नए उद्योगों को मंजूरी; 1900 से ज्यादा रोजगार मिलेंगे

मध्यप्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर तेजी से उभर रहे Pithampur स्थित Indore Special Economic Zone को एक और बड़ी सौगात मिली है। इंदौर स्पेशल इकोनॉमी जोन (SEZ) में चार नए बड़े उद्योगों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे क्षेत्र में निवेश, रोजगार और निर्यात की संभावनाएं और मजबूत होंगी।

इन नई परियोजनाओं के जरिए कुल 2,245.50 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लगभग 1,910 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इसके साथ ही अगले पांच वर्षों में 20,433 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है। यह मंजूरी SEZ की यूनिट अप्रूवल कमेटी की बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता Abhishek Sharma ने की।

बैठक में MPIDC के कार्यकारी संचालक Himanshu Prajapati, आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी और संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में जिन उद्योगों को स्वीकृति मिली, उनमें मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की इकाइयां शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये निवेश इंदौर SEZ को देश के प्रमुख निर्यात-उन्मुख औद्योगिक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत बनाएंगे। सबसे बड़ी मंजूरी Ajanta Pharma की नई विनिर्माण इकाई को मिली है। कंपनी को 25 एकड़ भूमि पर 674 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति दी गई है।

भोपाल पुलिस में बड़ा एक्शन

TI की लापरवाही पर 50 हजार का जुर्माना

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कानून व्यवस्था के मामलों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कोहेफिजा थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी (TI) कृष्ण गोपाल शुक्ला पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

यह कार्रवाई जिलाबदर किए गए एक बदमाश पर कथित मेहरबानी और कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही पाए जाने के बाद की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि जिलाबदर आदेश के बावजूद आरोपी की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी नहीं रखी गई। समय पर कानूनी कार्रवाई नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। मामले की समीक्षा के बाद पुलिस आयुक्त ने इसे अनुशासनहीनता और गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित अधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया। सूत्रों के अनुसार, पुलिस मुख्यालय ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हुई

अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं।

यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को कल सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से 2,510 पहलगाम मार्ग से और 2,312 बाल्टल मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।